**भारत सरकार**

**शिक्षा मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2472**

उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

**लक्षद्वीप में एनईपी 2020 का अनुपालन न होना**

**†2472. श्री हमदुल्ला सईद:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लक्षद्वीप में शिक्षा विभाग एक पुराने प्रशासनिक ढांचे के साथ काम कर रहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप नहीं है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार शिक्षा निदेशालय को प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए दो विशिष्ट इकाइयों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रशासनिक ध्यान केन्द्रण और जवाबदेही में सुधार के लिए समर्पित सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पुनर्गठन को लागू करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा और रणनीति क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क): शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण के साथ सक्रिय रूप से अनुकूलित हैं तथा उन्होंने चरणबद्ध और संरचित तरीके से इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कई पहल की हैं। मुख्य सुधारों में सीबीएसई को नामित प्राधिकारी के रूप में राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना, निपुण भारत के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) मिशन का कार्यान्वयन, सभी नर्सरी स्कूलों में बाल वाटिका कक्षाओं की शुरूआत, और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार बैगलेस दिवस का पालन शामिल है। सभी स्कूलों में समग्र प्रगति कार्ड शुरू किए गए हैं, तथा एनईपी और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के आधार पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए नियमित अभिविन्यास और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। सहकार्यता को

प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न द्वीपों के स्कूलों को स्कूल परिसरों में पुनर्गठित किया गया है, जबकि पाठ्यक्रम सुधारों में एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को अपनाना, गतिविधि-आधारित शिक्षा तथा कक्षा 5 और 8 के लिए ब्रिज कार्यक्रम शामिल हैं। ये प्रयास संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की भौगोलिक और लॉजिस्टिकल चुनौतियों के बावजूद प्रगतिशील और संदर्भ-संवेदनशील एनईपी कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

(ख): शिक्षा निदेशालय, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करता है, जो स्कूल स्तर पर एकीकृत योजना और समन्वय सुनिश्चित करता है। इस एकीकृत संरचना के अंतर्गत कार्यात्मक प्रभाग मौजूद हैं, जिनमें समर्पित विंग और नामित नोडल अधिकारी एनईपी 2020 के अनुरूप जिम्मेदारियां संभालते हैं। पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षणशास्त्र, शिक्षक विकास, डिजिटल पहल, प्रशिक्षण और डेटा प्रणाली सभी की योजना चरणवार बनाई गई है।

(ग): जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल निगरानी की जिम्मेदारियां प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और क्लस्टर संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को सौंपी गई हैं, जिनमें से सभी को एनईपी कार्यान्वयन का सहयोग करने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। एफएलएन, समग्र प्रगति कार्ड और एनसीएफ-आधारित पाठ्यक्रम सहित विभिन्न विषयों में विषय संसाधन समूह बनाए गए हैं, जबकि निदेशालय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी चरण-विशिष्ट पर्यवेक्षण का कार्य संभालते हैं। नियमित शैक्षणिक लेखापरीक्षा, निरीक्षण और समीक्षा पारदर्शिता और एनईपी उद्देश्यों के साथ अनुकूलन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

(घ): शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, शिक्षा निदेशालय, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप वर्ष 2021 से एनईपी के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन मॉडल का पालन कर रहा है। प्रारंभिक चरण में अभिविन्यास और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसके बाद वर्ष 2022 में निपुण भारत और बुनियादी मूल्यांकन का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2023 में, बैगलेस दिवसों के कार्यान्वयन के साथ-साथ बाल वाटिका कक्षाएं, डिजिटल शिक्षण पहल और एनईपी-अनुकूलित शिक्षक प्रशिक्षण शुरू किया गया। वर्ष 2024 में समग्र प्रगति कार्ड के संचालन और स्कूलों को एनसीएफ-आधारित पाठ्यक्रम के प्रति उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भविष्य की कार्यनीतिक प्राथमिकताओं में डिजिटल मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करना, स्कूल नेतृत्व के लिए क्षमता निर्माण, स्थानीय पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री का विकास, तथा हरित और समावेशी स्कूल शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

*****